

प्रेषक,

डा० निधि पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी, नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग-7 (उच्च शिक्षा)

देहरादून दिनांक 29 मार्च, 2012

विषय:- वित्तीय वर्ष 2011-2012 में राजकीय महाविद्यालय लम्बगॉव में बी०एड० संकाय भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या डिग्री विकास /13762/2011-12 दिनांक 16.12.2011 के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय महाविद्यालय लम्बगॉव में बी०एड० संकाय भवन निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में द्वितीय चरण हेतु गठित प्राक्कलन के सापेक्ष टी०ए०सी० वित्त विभाग के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी ₹ 241.44 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि के सापेक्ष ₹ 45.45 लाख की (₹ पैतालिस लाख पैतालिस हजार मात्र) धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त की जायेगी।

3- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण लो०नि०वि० के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

4- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

5- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लो०नि०वि० द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

6- कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

7- मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047 /xiv-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

- 8- यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाय।
- 9- कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश संख्या 475/xxvii(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 में निर्धारित प्रारूप पर कार्यदायी संस्था के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित करवाते हुये एक प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 10- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 571/xxvii(1)/2010 दिनांक 19-10-2010 में निदृष्ट दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) स्वीकृति हेतु शासन को उपलब्ध करायी जाय।
- 11- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्यय की अनुदान सं० 11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखा शीर्षक -4202-शिक्षा खेल कूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा -203-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-आयोजनागत-00-13 सोसाइटी मोड में स्ववित्त पोषित बीएड कक्षाओं का संचालन-24-वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 12- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 452 (p)/xxvii (3)/2011-12 दिनांक 29 मार्च, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीया,

(डा० निधि पाण्डेय)
अपर सचिव

सं० 2252 (1)/xxiv(7)28(2)/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- आयुक्त कुमाऊँ मण्डल पौड़ी।
- 3- जिलाधिकारी, टिहरी।
- 4- कोषाधिकारी ~~देहरादून~~।
- 6- वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय।
- 7- निदेशक एनओआईसीओ उत्तराखण्ड।
- 8- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
- 9- वित्त अनु०-3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
- 10- कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल निगम नई टिहरी।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(विदीराम)

अनु सचिव